गुजरात में डाकघर

1961. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992, की स्थिति के अनुसार गुजरात के कितने गांवों में डाकघर नहीं थे ;

(ख) वहां डाकघर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में गुजरात में जिला-वार कितने कितने डाकघर खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) 31-3-92 की स्थिति के अनुसार गुजरात के ऐसे गांवों की कुल संख्या 10779 है, जिनमें डाकघर नहीं हैं ।

(ख) देश के सभी गांवों में, जिनमें ऐसे गांव भी शामिल हैं जिनमें डाकघर नहीं हैं, डाक वितरण सहित मूलभूत डाक सुविधाएं उपलब्ध हैं । वार्षिक योजना 1991-92 के दौरान गुजरात में उनासी शाखा डाकघर और तीन विभागीय उप-डाकघर खोलने की मंजूरी दी गई । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में और अधिक डाकघर खोलकर डाक सुविधाओं की उपलब्धता में आये सुधार किया जाएगा ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समूचे देश में 3000 शाखा डाकघर और 500 विभागीय उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है और गुजरात राज्य में भी डाक के विकास की उसकी मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित संख्या में डाकघर खोले जाएंगे । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में खोले जाने के लिए प्रस्तावित डाक-घरों की जिलावार संख्या गुजरात सर्किल को आबंटित लक्ष्यों के अनुसार एक के बाद एक वार्षिक योजनाओं में निश्चित की जाएगी इस संबंध में विवरण 1992-97 तक की एक के बाद एक वार्षिक योजना पर अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद ही उपलब्ध होगा । वार्षिक योजना 1992-93 के दौरान गुजरात में पच्चीस शाखा डाकघर और पांच विभागीय उप-डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है बशर्ते कि निर्धारित मानदंड पूरे हों और धनराशि उपलब्ध रहे ।

टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन

1962. **डा० अबरार अहमद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1991 के बाद किन-किन राज्यों और जिलों में टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया गया है और उक्त समितियों में अब तक कितने व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है,

(ख) क्या ऐसी समितियों की सदस्य-संख्या के रूप में कोई अधिकतम अथवा न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है, यदि हां, तो इस प्रकार निर्धारित की गई सीमा क्या है,

(ग) उक्त समितियों के गठन के फल-स्वरूप मंत्रालय के व्यय में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है,

(घ) किन-किन राज्यों और जिलों में टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया जाना शेष है और इनका गठन कब तक कर दिया जायेगा, और

(ङ) क्या सरकार का, उक्त समितियों के लिए नाम-निर्देशित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को निर्धारित करने का विचार है ताकि विभिन्न स्थानों पर ऐसी समितियों को अपने बड़े आकार के कारण अव्यवहारिक होने से बचाया जा सके ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जून 1991 के बाद जिन राज्यों तथा जिलों में दूर संचार टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया गया है उनके नाम तथा उन समितियों के लिए नामित व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा